भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय **लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या +1370** दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत अवसंरचना हेतु निधि

+1370. श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्री राजेश वर्मा:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्रीमती शांभवी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य-वार कुल कितनी निधि स्वीकृत, संवितरित और उपयोग की गई है;
- (ख) क्या नवनिर्मित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदत्त सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कंप्यूटरों के आवंटन से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल साक्षरता में सुधार आया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या विगत तीन वर्षों में ग्राम पंचायत कार्यालयों के निर्माण के दौरान पारिस्थितिकी-अनुकूल सामग्रियों अथवा टिकाऊ अवसंरचना निर्माण को प्राथिमकता दी गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) 'पंचायत', राज्य का विषय होने के कारण, पंचायतों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, पंचायतों के राजस्व के अपने स्रोत आदि सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाएँ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायतें प्रभावी रूप से काम कर सकें।

तथापि, वर्ष 2022-23 से 2025-2026 तक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत, मंत्रालय ग्राम पंचायतों के प्रभावी कामकाज के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सीमित पैमाने पर पूरा करता है जैसे कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, जीपी भवनों और कंप्यूटरों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का सह-स्थापन, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित किया जाता है और बाद में केंद्रीय

अधिकार प्राप्त सिमिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों, कंप्यूटरों और सीएससी सह-स्थापन के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि का विवरण **अनुबंध-1** में है।

(ख) और (ग) ग्राम पंचायत भवन प्रभावी सेवा वितरण के लिए पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों में संस्थागत तंत्र की स्थापना और पंचायती राज संस्थान/ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अतिरिक्त, पंचायत भवनों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर का सह-स्थापन जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण में और सुधार करता है। इसी तरह, ग्राम पंचायतों के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर में कंप्यूटर की उपलब्धता पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अपने ई-एमएमपी (ई-मिशन मोड प्रोजेक्ट) के तहत विकसित विभिन्न ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर पंचायतों द्वारा ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंच और प्रभावी काम करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, त्वरित और पारदर्शी कामकाज को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय ने ई-पंचायत एमएमपी के तहत पंचायती राज संस्थानों के लिए एक ईआरपी प्लेटफार्म विकसित किया है। इस एप्लीकेशन में पंचायत के कामकाज के सभी पहलू जैसे कि ऑनलाइन भुगतान सिहत एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजना, बजट, लेखांकन, निगरानी, पिरसंपत्ति प्रबंधन आदि शामिल हैं। लगभग सभी ग्राम पंचायतें ईग्रामस्वराज के विभिन्न मॉड्यूल पर शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 2.41 लाख ग्राम पंचायतें ने 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के साथ व्यय के लिए ऑनलाइन लेनदेन पूरा कर लिया है। ई-ग्रामस्वराज पर ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतों का विवरण अनुबंध-॥ में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय के पास इस मामले पर कोई विशेष जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत कार्यालयों के निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों और स्थायी प्रथाओं को शामिल करना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों के अनुसार अलग-अलग है।

अनुबंध -।

दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1370 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पंचायत भवनों के निर्माण, कंप्यूटरों और सीएससी सह-स्थापन के लिए स्वीकृत धनराशि की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंचायत भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि				नी सह-स्थ स्वीकृत ध		कंप्यूटरों की खरीद		
		2022	2023	2024	2022	2023-	2024-	2022	202	202
		-23	-24	-25	-23	24	25	-23	3-24	4-2
										5
1	आंध्र प्रदेश	0	0	40	20	0	0	2.5	2.5	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	181.1	103.3	128.5	44.22	27	12.12	4	2	3
3	असम	52.2	60.3	64.3	8.75	3.5	0	2.5	2.5	3.44
4	बिहार	100	56	27.2	10	10	10	1.07	1.33	1.34
5	छत्तीसगढ	6.21	0	27.15	7.85	0	3	0	3	4
6	गोवा	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	76.6	0	1.8	23.65	0	0.45	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	58.4	20.2	18.2	77.4	26.8	21.25	1.67	0	0
10	झारखंड	0	0	0	6	0	0	0.96	0	10.3
										3
11	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	केरल	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	0	10	0	0	0	0	0	2.02
14	महाराष्ट्र	21.64	87.8	87.7	0.34	0	0	0	0	4.73
15	मणिपुर	4.9	2.2	2.2	0.75	0.75	0.75	0.3	0.3	0.41
16	मेघालय	6	6	4.8	4.6	4.6	4.6	5.98	8.48	8.38
17	मिजोरम	49.2	66	62.6	2.5	5	7.4	2.96	2.96	2.87
18	नागालैंड	10.68	26.8	26.8	0	0	0	1.22	1.22	1.73
19	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.5
20	पंजाब	51.8	17.8	0	0	0	0	0	0	1.5
21	राजस्थान	8.6	5.77	2.4	7.08	2.82	0.33	6.22	0	0
22	सिक्किम	4.5	4	3.4	1.5	1.5	2	0.93	0.25	0.25
23	तमिलनाडु	0	0	29.2	23	23	23	0	0	0
24	तेलंगाना	135	20	26.28	2.4	3	7.45	7.25	9.06	9.08
25	त्रिपुरा	4.4	3.99	2.94	1.15	1.2	1.2	2.37	2.6	2.6
26	उत्तर प्रदेश	49.33	31.13	21.34	230.6	176.51	156.58	15.72	10.8	0
									9	
27	उत्तराखंड	20	39	37.9	5	10	8.65	0	2.5	13.7
										2
28	पश्चिम बंगाल	0	7	19.32	0	0	0	0	0	0.56
29	जम्मू एवं कश्मीर	104.6	100	85.63	55.3	55.3	54.3	1.59	2.36	2.36

30	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.6	0	0.8	0	0	0	0	0	0.02
32	लद्दाख	0	0	0.6	0	0	0.15	0.32	0.3	0.3
	कुल		659.5	650.	532.4	350.9	313.2	57.56	52.5	75.6
		6	9	64	1	8	3			4

दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1370 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

वित्तं वष 2024-25 के दारान पंचायत स्तर पर इ-ग्रामस्वराज का अपनाना										
क्र.स ं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचाय तों एवं समक क्ष की कुल संख्या	ग्राम पंचाय त शामि ल	ऑन लाइन भुगता न करने वाली ग्राम पंचाय तें और समक क्ष	ब्लॉक पंचाय तों की कुल संख्या	ऑन बोर्ड ब्लॉक पंचाय त	ऑन लाइन भुगता न करने ब्लॉक पंचाय तें	जिला पंचाय तों की कुल संख्या	ऑन बोर्ड जिला पंचाय त	ऑन लाइन भुगता न करने वाली जिला पंचाय तें
1	आंध्र प्रदेश	1332 8	13296	1290 7	660	660	639	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	185	0	0	0	25	25	7
3	असम	2662	2197	2170	191	191	185	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8044	534	534	529	38	38	38
5	छत्तीसगढ	1159 6	11594	1150 3	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	191	89	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	1465 6	14594	1366 6	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6221	5829	143	143	131	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3509	81	81	80	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4317	264	264	262	24	24	23
11	कर्नाटक	5954	5954	5935	238	232	117	31	31	28
12	केरल	941	941	940	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	2301 1	23009	2297 3	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	2791 1	27834	2626 8	351	351	302	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	120	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6792	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	1323 7	13222	9173	152	151	110	22	22	19
21	राजस्थान	1121 1	11206	1073 9	361	353	351	33	33	33

क्र.स ं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचाय तों एवं समक क्ष की कुल संख्या	ग्राम पंचाय त शामि ल	ऑन लाइन भुगता न करने वाली ग्राम पंचाय तें और समक क्ष	ब्लॉक पंचाय तों की कुल संख्या	ऑन बोर्ड ब्लॉक पंचाय त	ऑन लाइन भुगता न करने ब्लॉक पंचाय तें	जिला पंचाय तों की कुल संख्या	ऑन बोर्ड जिला पंचाय त	ऑन लाइन भुगता न करने वाली पंचाय तें
22	सिक्किम	199	199	194	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	1252 5	12525	1251 8	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	1277 1	12768	1262 8	540	540	498	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1176	1162	75	75	75	9	9	8
26	उत्तराखंड	7795	7794	7729	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	5769 1	57691	5759 6	826	826	821	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		2634 81	2518 53	2411 56	8658	6402	6098	650	642	609
